**Supply of 100 MW power to Assam by NTPC**

2030. SHRI JIBON ROY:
SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any agreement was to be signed in May 1995 to supply 100 MWs power by NTPC to Assam;

(b) whether the same could not materilize as NTPC insisted on RBI guarantee while it was not insisted for other SEBs;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) by when terms for supply of power to such sensitive areas would be made easier?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir. An agreement between NTPC and ASEB was signed in May, 1994 for supply of 100 MWs of power.

(b) to (d) Since the ASEB owed substantial amounts to NTPC on account of supply of power, NTPC had insisted on additional securities before giving effect to the above agreement. Such safeguards were considered prudent by NTPC which has convenants with its leders to keep its receivables position within manageable limits. However, since 28th February, 1997. NTPC has started supply of about 100 MW of extra power to ASEB on an assurance from it that a letter of credit would be opened in favour of NTPC by ASEB within a week's time.

**In-Principle Clearance of Power Projects**

2031. SHRI JIBON ROY:
SHRI RAMCHANDRAN PILLAI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) project by CEA involves preliminary clearance pertainng to fuel allocation, water availability, clearance of Sate Pollution Control Boards, and other preferability requisities;

(b) if not, the steps involved in IPC;

(c) the number of cases since 1992, where IPC was not found necessary and CEA was asked to process the detailed projects reports; and

(d) the names of these projects and their status?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI):

(a) Yes, Sir.

(b) Does not arise in view of reply to (a) above.

(c) and (d) Central Electricity Authority (CEA) had been advised not tc entertain any proposal on the Memorandum of Understanding/Letter of Intent, etc., route costing more than Rs. 100 crores for accord of 'in-principle' after 31.3.1996. However, in the case of the folowing four proposals, taking into consideration the fact that they had been rcommended by the concerned State Governments and that some of the promoters had made reasonably good porogress on their proposals, and the delay in submission of the feasibility reports to CEA was entirely due to reasons beyond the control of the IPP, 'in-principle' clearance was not found necessary and CEA was asked to examine the proposals for accord of techno-economic clearance:—

| Sl. No. | Name of the Project | Capacity (MW) |
|---|---|---|
| 1. | Bangalore Thermal Power Project. M/s NRI Capital Corporation | 500 |
| 2. | Dharwad Thermal Power Project, M/s Wesco Power Generation Ltd. | 300 |

| Sl. No. | Name of the Project | Capacity (MW) |
|---|---|---|
| 3. | Naraj Thermal Power Project. M/s Orissa Power Partners Ltd. | 2×2.50 |
| 4. | Gouripur Thermal Power Project, M/s Gouripur Power Co. Ltd. | 150 |

The promoters of all the above schemes are required to submit their Detailed Project Report (DPR) by 31.3.1997 to CEA for obtaining the techno-economic clearance.

**विंध्याचल विद्युत परियोजना के लिए एश-डायक के निर्माण हेतु ठेका**

2032. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1000 मेगावाट वाले विद्युत संयंत्र के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये का ठेका एश-डायक के निर्माणार्थ दिया गया है, जो एन० टी० पी० सी० विंध्याचल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण में है, जो विंध्यय नगर, जिला-सीधी, मध्य प्रदेश में स्थित है, यदि हां, तो यह ठेका किस व्यक्ति/पार्टी को प्रदान किया गया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्ययोजना के लम्बित होने के बावजूद भी, संबंधित कम्पनी के मालिक को अग्रिम राशि के रूप में चार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है तथा अक्तूबर, .1994 से प्रतिमाह दस लाख रुपये का भुगतान दिया जा रहा है, और यह भुगतान लगभग अठ्ठाईस महीनों से किया जा रहा है, यद्यपि कम्पनी ने कोई कार्य नहीं किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी):** (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण (1000 में वा०) के लिए प्रतियोगी राख कुण्ड पैकेज के निर्माण कार्य का ठेका अभी तक प्रदान नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**विध्याचल विद्युत परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता**

2033. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एन.टी.पी.सी. विध्याचल विद्युत परियोजना, विध्य नगर जिला सीधी (मध्य प्रदेश) के लिए चार ग्रामों-चुड़चुड़िया, अमरातली, अस्का एवं जुड़ी के लगभग पांच सौ व्यक्तियों की तीन सौ एकड़ निजी भूमि को अधिगृहीत किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास हेतु विश्व बैंक से लगभग साढ़े तीन व्यक्तियों की तीन सौ एकड़ निजी भूमि को अधिगृहीत किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास हेतु विश्व बैंक से लगभग साढ़े तीन करोड़ रूपये की ऋण-राशि सहायतार्थ प्रदान की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1993 में पुनर्स्थापना और पुनर्वास हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी):** (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने मध्य प्रदेश में सीधी जिले के विधा नगर में अपनी विन्ध्याचल विद्युत परियोजना के लिए चुड़चुड़िया, अम्रातली, अस्का तथा खुडी नामक चार गांवों के लगभग 824 लोगों को 613.15 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**Hydel power projects in Tamil Nadu**

2034. SHRI T.M. VENKATACHALAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made any survey to study unexploited sources of hydel power generation in the country;